ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(1): 980-983
www.allresearchjournal.com
Received: 25-11-2016
Accepted: 26-12-2016

अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

पूर्णियाँ जिला ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अनामिका कुमारी

सारांशः
किसी भी देश के विकास का आंकलन उस देश की जनता के जीवन स्तर से किया जाता है। सामान्यतः जनता के जीवन स्तर में समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के जीवन स्तर के मानक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लगभग सभी विकासशील देशों में महिलाएँ समाज का कमजोर हिस्सा है और प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे अपने भारतीय प्रसंग में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि महिलाओं की स्थिति ही देश के वास्तविक स्वरूप का परिचायक है। डॉ. बी.एम. शर्मा (1999) का कहना है मानव सभ्यता के ऊषाकाल से ही मानव समाज के निर्माण एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अथवा यूं कहे कि समाज के निर्माण एवं विकास को सजाने एवं संवारने में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की भूमिका अधिक रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज महिला वर्ग की भूमिका एवं महता को नजरअंदाज कर विकास की दौड़ में आगे नहीं आ सकता।

प्रस्तावनाः
महिला विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। 1980 की पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास को अलग–अलग समूह के रूप में मान्यता देकर उन्हें विकास योजना में समुचित स्थान दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्या के प्रति जो कल्याणकारी दृष्टिकोण रखा जाता था उसके स्थान पर अब उनके विकास तथा उन्हें अधिक अधिकार देने पर बल दिया गया। महिलाओं को अधिकार देने के सरकार के सभी प्रयासों का उद्देश्य उसका सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनैतिक स्तर की दृष्टि से पुरूषों के समान ऊपर उठाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है।
महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनमें मुख्य रूप से बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यवाही की योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, महिला विकास कार्यक्रम, सामूहिक विकास प्रोत्साहन कार्यकम, विधवा स्त्री की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, विकलांग विवाह अनुदान, जिला महिला सहायता समिति, किशोर बालिका योजना, 'लाडली' किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना (स्वयंसिद्ध) स्टेट लेवल स्फिटिंग एवं रिव्यू कमेटी का गठन, अल्पवास गृह योजना, कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण, महिलाओं में प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) महिला नीति, महिला शक्ति अवार्ड, महिला आयोग, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ कार्यक्रम, नरेगा, एकीकृत ग्राम विकास योजना (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, इन्दिरा महिला योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।
ग्रामीण विकास की योजनाएं का महिलाओं पर प्रभाव से संबंधित कुछ पूर्ववर्ती अध्ययन इस प्रकार है –
शैलेन्द्र मौर्य ने अपने अध्ययन में बताया कि महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। कपूर तथा सिंह (1997) ने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण, महिला, बच्चे, बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, चेतना, जागृति आदि क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान का अध्ययन किया। देवी (1997) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि व्यक्तियों के स्थान पर समूहों को सहायता प्रदान की जाए और कार्यक्रमों को प्रभावी व उपयुक्त बनाने के लिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये। संगीता शर्मा (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि केन्द्र व राज्यों

की सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। मंजू जैन (1994) कार्यशील महिलाओं के अपने अध्ययन में पाया कि कार्यशील महिला पारिवारिक तथा कार्यस्थल के दायित्वों के समन्वय हेतु सक्षम है। के.सी. विद्या (1997) ने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में आनुभाविक अध्ययन किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पूर्णियाँ जिला की महिलाओं की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का पता करना।
2. विकास योजना द्वारा पूर्णियाँ जिला की महिलाओं को मिले लाभ व योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत होना।
3. सरकारी योजनाओं का पूर्णियाँ जिला की महिलाओं के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिहार राज्य के पूर्णियाँ जिले के विभिन्न पंचायत समिति का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया। विभिन्न ग्रामीण इलाके में 200 ग्रामीण महिलाओं का चयन सरल दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन आदि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्त्रोतों से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है। उपलब्धियाँ

तालिका 1: महिला विकास हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	136	68
जानकारी नहीं है	64	32
योग	200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत सूचनादात्रियों को ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी है। 32 प्रतिशत ने इससे अनभिज्ञता प्रकट की।

तालिका 2: सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी योजनाएँ

योजनाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
मनरेगा	30	15
वृद्धावस्था पेंशन	36	18
भामाशाह योजना	20	10
स्वास्थ्य योजना	14	07
आंगनबाडी योजना	32	16
पोषाहार	20	10
परिवार कल्याण कार्यक्रम	06	03
महिला समृद्धि योजना	22	11
द्वारका योजना	16	08
अपनी बेटी अपना धन योजना	04	02
योग	200	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15प्रतिशत सूचनादात्रियाँ मनरेगा, 18 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ भामाशाह योजना, 07 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ स्वास्थ्य योजना तथा 16 प्रतिशत सूचनादात्रियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी योजना की जानकारी है। सामाजिक सहायता, पोषाहार, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना एवं द्वारका योजना भी ग्रामीण महिलाओं में लोकप्रिय है। सबसे कम सूचनादात्रियों को अपनी बेटी अपना धन योजना की जानकारी है। इस प्रकार ज्यादातर सूचनादात्रियों को महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी है।

तालिका 3: सरकारी योजनाओं से जुड़ने के कारण

कारण	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
आर्थिक	76	38
समय का सदुपयोग	34	17
आत्म निर्भरता	84	42
अन्य	06	03
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 38 प्रतिशत सूचनादात्री आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी 17 प्रतिशत महिलाएँ खाली समय का सदुपयोगस करने, 42 प्रतिशत महिलाएँ आत्म निर्भर होने हेतु तथा 03 प्रतिशत महिलाएँ समाज सेवा व अन्य कार्यों से प्रेरित होकर सरकारी योजनाओं से जुड़ी। इस प्रकार आर्थिक कारण व आत्म निर्भरता ही सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मुख्य प्रेरणास्रोत रहा है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएँ किसी न किसी कारण से नियोजनाओं से जुड़ रही है और इनका लाभ भी उठा रही है।

तालिका 4: लाभान्वित महिलाओं में आई अधिकारों की प्रति जागरूकता

जागरूकता	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
आयी है	76	38
नही आयी है	34	17
योग	**200**	**100**

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं में लाभान्वित होने के बाद उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है तथा अब वह अपने अधिकारों को समझने लगी है। 6 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने

बताया कि उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं आई क्योंकि वह इन योजनाओं के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाई है। इस प्रकार कार्य के दौरान व सरकारी विभागों में विभिन्न लोगो से सम्पर्क के दौरान महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जानकारी, चेतना व जागरूकता पैदा हुई है। अब वह इनके प्रति सतर्क और जागरूक है।

तालिका 5: सरकारी योजनाओं से उठाया गया लाभ योजनाएँ

योजनाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
वृद्धावस्था पेंशन	90	45
नरेगा	38	19
शौचालय	14	07
इंदिरा आवास	26	13
पन्नाधाय छात्रवृत्ति	20	10
पालनहार	08	04
अन्य	04	02
योग	200	100

उपरोक्त तालिका के आँकडे दर्शाते है कि 45 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना, 19 प्रतिशत महिलाएँ नरेगा योजना, 07 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ स्वच्छ शौचालय, 13 प्रतिशत महिलाएँ इंदिरा आवास, 13 प्रतिशत महिलाएँ पन्नाधाय छात्रवृत्ति, 04 प्रतिशत महिलाएँ पालनहार योजना तथा 02 प्रतिशत महिलाएं अन्य विभागों की योजनाओं में लाभान्वित हुई। इस प्रकार अधिकतर सूचनादात्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ उठाया है जिससे उनको प्रतिमाह एक मुश्त राशि प्राप्त होती रहती है। बाकी योजनाओं के प्रति भी उनका रूझान धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है।

तालिका 6: लाभान्वितों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ

कठिनाइयाँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पूरी राशि का भुगतान नहीं	30	15
बार-बार चक्कर काटे	106	53
कर्मचारियों का असहयोग पूर्ण रवैया	54	27
अन्य	10	05
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिशत सूचनादात्रियों को सरकारी विभागों द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 53 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी विभागों के बार–बार चक्कर लगाने पड़े, 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों के प्रति सरकारी विभागों के कर्मचारियों का असहयोगपूर्ण रवैया रहा था। ***0***05 प्रतिशत महिलाओं में रिश्वत, भ्रष्टाचार व अन्य कारणों को उत्तरदायी बताया है। इस प्रकार सूचनादात्रियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

तालिका 7: विकास योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

बाधाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त राशि न मिलना	96	48
ऊँची ब्याज दर	03	1.50
सहायता में देरी	58	29
भ्रष्टाचार	28	14
माल के विक्रय की व्यवस्था न होना	08	04
अनुत्तरित	07	3.50
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 48 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि विकास योजनाओं द्वारा पर्याप्त राशि नहीं मिलती, 1.50 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं द्वारा ऊँची ब्याज दर पर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 29 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं में आर्थिक सहायता देरी से उपलब्ध होती है। 14 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आर्थिक ऋणसहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि गाँवों में कृषि उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पादित माल का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। 3.50 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर आया है कि योजनाओं के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन हेतु उनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही क्षेत्र में योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने की भी आवश्यकता है। यदि सरकारें इन कमियों की तरफ ध्यान दे तो यह योजनाएँ अधिक प्रभावी हो सकती है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

तालिका 8: योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव

सुझाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अधिकारियों व कर्मचारियों की सोच में बदलाव	54	27
भ्रष्टाचार दूर करना	70	35
राजनेता, प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप दबाव में कमी लाना	08	04
जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास	46	23
क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाना	08	04
साधन व सुविधा बढ़ाना	14	07
योग	**200**	**100**

इस तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों महिलाओं की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की सोच में बदलाव लाना जरूरी समझती है। 35 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को दूर किया जाना आवश्यक है। 12 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि राजनेताओं

एवं प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप व दबाव में कमी लाई जाए तभी यह योजनाएँ सफल होगी। 23 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जाए। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने कहा कि क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाई जावे जबकि 07 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साधन एवं सुविधाएँ बढाई जाए। अतः अधिकांश सूचनादात्रियों ने महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता बताई है।

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश सूचनादात्रियों को ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, भामाशाह कार्ड, स्वास्थ्य आंगनवाडी, पोषाहार, महिला समृद्धि योजना की जानकारी है। सूचनादात्रियाँ आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। महिलाएँ वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, स्वच्छ शौचालय इंदिरा आवास, पन्नाधाय छात्रवृत्ति, पालनहार जैसी योजनाओं से लाभान्वित भी हुई है। सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें सरकारी विभागों द्वारा पूरी स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। सहायता हेतु बार–बार सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते है, कर्मचारियों का उनके प्रति असहयोगपूर्ण रवैया रहता है।

विकास योजनाओं का सही लाभ मिले इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण एवं लाभ की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जानी चाहिए, लोगो का सरकारी विभाग व अधिकारियों से सीधा संवाद हो व प्रचार–प्रसार द्वारा लोगो में जागरूकता पैदा की जावे। सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें कार्य के बदले पूरा भुगतान न मिलना, ऋण पर ऊँची ब्याज दर, सहायता में देरी, भ्रष्टाचार तथा उत्पादित माल के विपणन की पर्याप्त व्यवस्था का न होना योजनाओं के मार्ग की बाधां है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की सोच में बदलाव, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण, राजनेता एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप व दबाव को बन्द किया जावे, जनभागीदारी बढ़ाने के प्रयास, क्षेत्रीय गुटबाजी के कमी और साधन सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि गुटबाजी, दखलअंदाजी और भ्रष्टाचार इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बने हुए है, जब तक इनको दूर करने के प्रयास नहीं किए जायेंगे तब तक जन–जन तक इनका लाभ नहीं पहुँच पाएगा।

निष्कर्ष

सूचनादात्रियाँ महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सन्तुष्ट पाई गई। अधिकतर सूचनादात्रियों ने योजनाओं का निर्माण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन के स्तर पर जनसहभागिता को महत्वपूर्ण माना है। सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक सुरक्षा, आत्म विश्वास में वृद्धि, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, उन्नत जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। इस प्रकार सूचनादात्रियों के जीवन में सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आया है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की महती भूमिका है।

संदर्भ

1. शर्मा, बी.एम. (1999) भारत में महिला सशक्तिकरण मूल प्रश्न, उदयपुर पृ. 70
2. मौर्य, शैलेन्द्र (2007) राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक, राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर पृ. 117
3. कपूर ए.के. सिंह, धर्मवीर (1997) रूरल डेवलपमेन्ट एन.जी. ओ. रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ. 99
4. देवी, मंजू के.(1997) रूरल वूमेनः पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनमोल पब्लिकेशन प्रा.लि.नई दिल्ली पृ. 24
5. शर्मा, संगीता (2005) महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन, जयपुर।
6. जैन, मंजू (1994) कार्यशील महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवेल, जयपुर, पृ.144
7. विद्या, के.सी. (1997) पालिटिकल एम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन एट द ग्रास रूट, कनिष्ठ पब्लिशर्स, नई दिल्ली